राष्ट्रपति के 2019 के अभिभाषण के मुख्य अंश

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 31 जनवरी, 2019 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रमुख नीतिगत उपलब्धियों को रेखांकित किया। अभिभाषण के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

अर्थव्यवस्था

- पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था औसत 7.3% की दर से बढ़ रही है। भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
- 2014 में विश्व की जीडीपी में भारत का योगदान 2.6% था। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 में यह बढ़कर 3.3% हो गया।
- इनकम टैक्स के बोझ को कम करके और मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रण में रखकर सरकार ने मध्यम वर्ग की बचत को व्यापक बनाने के लिए नए अवसरों का सृजन किया है।

वित्त और बैंकिंग

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग के 21 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया। इन योजनाओं के अंतर्गत 3,100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि संवितरित की गई।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पेशेवर और कारोबारी जरूरतों के लिए ऋण प्रदान करती है। इसके अंतर्गत युवाओं को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण संवितरित किए गए।
- अब तक जन धन योजना के अंतर्गत 34 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। 2014 से 2017 के दौरान विश्व के विभिन्न देशों में जितने बैंक खाते खोले गए, उनमें से 55% खाते अकेले भारत में खोले गए।
- पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के विस्तार के परिणामस्वरूप, 6.05 लाख करोड़ से अधिक की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई है। इसके कारण लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है।

भ्रष्टाचार और काला धन

- भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए काले धन पर विशेष जांच टीम की स्थापना की गई है।
- विमुद्रीकरण के जरिए काले धन के प्रवाह के लिए जिम्मेदार 3.3 लाख फर्जी कंपनियों का पंजीकरण रद्द हुआ है।
- बेनामी संपत्ति एक्ट, प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट और भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है।

दक्षता विकास और रोजगार सृजन

- कौशल विकास अभियान शुरू किया गया। आने वाले वर्षों में देश में 15,000 से ज्यादा आईटीआई, 10,000 से ज्यादा कौशल विकास केंद्र और 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भारत के युवाओं के कौशल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना द्वारा सरकार ने नौकरियों को इंसेन्टिव के साथ जोड़ा है। ईपीएस और ईपीएफ में एम्पलॉयर की तरफ से 12% योगदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पहले तीन वर्ष तक यह योगदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ देश के एक करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिल चुका है।

स्वास्थ्य और स्वच्छता

- गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर इलाज के खर्च का बोझ कम करने हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत

ज़रका शब्बीर
zarka@prsindia.org

31 जनवरी, 2019

देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत देश के 50 करोड़ गरीब लोग के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में, हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए खर्च की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से ज्यादा लोग अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज करवा चुके हैं।
- देश के दूर-दराज और आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की है। इसके फलस्वरूप देश बहुत तेजी से 'सार्वभौमिक टीकाकरण' के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है।
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98% हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40% से भी कम था।

सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण

- पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान औसत हर महीने 140 सहायता शिविरों का आयोजन किया है, जहां पहुंचकर दिव्यांग जन उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान लगभग 12 लाख दिव्यांग जनों को 700 करोड़ रुपये के सहायता उपकरण दिए गए।
- दिव्यांग जनों को रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर होने वाली असुविधा को देखते हुए सरकार ने सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत लगभग एक हजार सरकारी इमारतों और 650 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को उनके लिए सुगम्य बनाया है।

शिक्षा

- उच्च स्तर की पेशेवर शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और सात आईआईटी, सात आईआईएम, 14 आईआईआईटी, एक एनआईटी और 4 एनआईडी की स्थापना की जा रही है।
- 103 केंद्रीय विद्यालय और 62 नए नवोदय विद्यालय बनाने की दिशा में कदम उठाकर शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती देने का काम किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ महिलाओं को प्रदान किए गए हैं। 15 करोड़ मुद्रा ऋणों में से 73% ऋण महिला उद्यमियों को संवितरित किए गए हैं।
- देश के छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों में महिला उद्मियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए अब बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे कम से कम 3% खरीदारी महिला उद्यमियों के प्रतिष्ठानों से ही करें।
- सरकार ने मातृत्व अवकाश को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है।

कानून और प्रशासन

- नागरिकता संशोधन बिल उन पीड़ितों की मदद करेगा जो भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए यहां शरण लेने के लिए मजबूर हुए।
- किसी नाबालिग के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए सरकार ने फांसी की सजा का प्रावधान किया है। सरकार तीन तलाक बिल को संसद से पारित करवाने का प्रयास कर रही है।

उद्योग और मैन्यूफैक्चरिंग

- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत जहां 2014 में 142वें स्थान पर था, वहीं अब 65 रैंक ऊपर आकर 77वें स्थान पर पहुंच गया है।
- मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े मेडटेक जोन की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं।

परिवहन और कनेक्टिविटी

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2019 तक हर गांव को सड़क कनेक्टिविटी देने का लक्ष्य रखा गया है। 82% से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है, जबकि 2014 में 56% गांव ही सड़कों से जुड़े हुए थे।
- 'उड़ान योजना' के अंतर्गत लोगों को 12 लाख सीटें कम कीमत पर उपलब्ध हुई हैं। इसके कारण आज आम लोगों को भी हवाई यात्रा का अवसर मिल रहा है।

शहरी और ग्रामीण विकास

- पिछले साढ़े चार वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। 2014 के पहले 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था।
- घरों का निर्माण समय पर पूरा हो, इसके लिए सरकार ने रियल ऐस्टेट (रेगुलेशन और विकास) एक्ट, 2016 को लागू किया। तब से लगभग 35,000 रियल ऐस्टेट प्रॉजेक्ट्स का पंजीकरण किया गया है।
- उज्ज्वला योजना के अंतर्गत छह करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए। पिछले चार वर्षों के दौरान गैस कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या 12 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ हो गई।
- 2014 में 18,000 से अधिक गांवों में बिजली कनेक्शन नहीं थे। आज हर गांव में बिजलीकरण हो गया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत 2.4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई है।

कृषि और जल संसाधन

- किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को फसल की लागत के डेढ़ गुना से अधिक पर निर्धारित किया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को कम प्रीमियम पर फसल बीमा प्रदान किया जा रहा है ताकि फसल खराब होने की स्थिति में उन्हें आने वाले संकट से बचाया जा सके।
- 'नमामि गंगे मिशन' के अंतर्गत अब तक 25,500 करोड़ रुपए मूल्य के प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। सरकार गंगा में गिरने वाले दर्जनों बड़े नालों को बंद करके, औद्योगिक कचरों को रोककर, शहरों के किनारे अनेक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान चला रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

- उड़ान योजना के अंतर्गत पूर्वी भारत में 19 नए हवाईअड्डे बनाए जा रहे हैं और इनमें से 5 पूर्वोत्तर में बन रहे हैं। सिक्किम में पाक्योंग हवाईअड्डा और ओडिशा के झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साय हवाईअड्डे का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है।
- पूर्वोत्तर की लगभग सभी रेल लाइनों को ब्रॉडगेज में बदला जा चुका है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 15 नई रेल लाइनों पर काम चल रहा है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।